

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, लखनऊ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएसएसआर) द्वारा उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त की स्थिति तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभिशासन पर परिसंवाद का आयोजन

लखनऊ, 25 मई 2026

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के कार्यालय द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएसएसआर) के सहयोग से दिनांक 25 मई 2026 को अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक मालवीय सभागार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक परिसंवाद का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य नोडल कार्यालय के रूप में, राष्ट्रीय सीएजी-आइसीएसएसआर परिसंवाद श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया गया।



परिसंवाद में दो महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक प्रासंगिकता के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया: "उत्तर प्रदेश के वित्त की स्थिति" तथा "सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन"। प्रथम विषय के अंतर्गत सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में परिलक्षित राजस्व प्रवृत्तियों, व्यय प्रतिरूपों, घाटा प्रबंधन तथा सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता सहित राज्य की राजकोषीय

स्थिति की विवेचना की गई। द्वितीय विषय, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना की पर्याप्तता तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी की प्रभावशीलता से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित रहा, जिसमें प्रणालीगत कमियों, शासन संबंधी चुनौतियों एवं तत्संबंधी नीतिगत अनिवार्यताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

परिसंवाद का शुभारंभ प्रो. धनंजय सिंह, सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के स्वागत उद्बोधन से हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था द्वारा सृजित ज्ञान को शैक्षणिक अन्वेषण एवं सार्वजनिक विमर्श से जोड़ने के महत्त्व पर बल दिया। श्री राजीव कुमार पाण्डेय, आइएएस, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने सभा को संबोधित किया तथा प्रारंभिक उद्बोधन डॉ. सुरेन्द्र कुमार, आइएएस, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रथम विषय के अंतर्गत डॉ. नागेन्द्र कुमार मौर्य, लखनऊ विश्वविद्यालय ने राज्य के राजकोषीय प्रबंधन एवं उसके व्यापक विकासात्मक निहितार्थों पर शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, तत्पश्चात् श्री राजीव कुमार पाण्डेय, आइएएस, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के वित्त की स्थिति पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। द्वितीय विषय के अंतर्गत डॉ. लोकेश चौधरी, आइएएस, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रस्तुत किए, तत्पश्चात् डॉ. नोमिता पी. कुमार, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति एवं शासन के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया। विषय-सत्रों के उपरांत एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसने वक्ताओं एवं श्रोताओं के मध्य सार्थक संवाद को प्रोत्साहित किया।

श्री पंकज वर्मा, आइएएस, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने उपस्थित जनों को सीएजी-आइसीएसएसआर शोध लेख प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराया। यह पहल विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं युवा अध्येताओं को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रारंभ की गई है। धन्यवाद ज्ञापन प्रो. हर्ष शर्मा, निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया गया।

परिसंवाद में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें लखनऊ विश्वविद्यालय, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, महर्षि विश्वविद्यालय ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसाबेला थोर्न कॉलेज तथा बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय सहित अनेक शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के शिक्षक, शोधार्थी, शोध-अभ्यर्थी एवं विद्यार्थी सम्मिलित थे।

लखनऊ परिसंवाद, चल रही सीएजी-आइसीएसएसआर परिसंवाद श्रृंखला का भाग है जो नवंबर 2025 से नवंबर 2026 के मध्य 28 राज्यों एवं 3 केंद्र-शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाली एक वर्षीय राष्ट्रीय पहल है। प्रत्येक परिसंवाद, संबंधित राज्य के पीएजी/एजी कार्यालय द्वारा आइसीएसएसआर के समन्वय से आयोजित किया जाता है, जिसमें राज्य-विशिष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं स्थानीय नीतिगत प्रासंगिकता के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

सीएजी-आइसीएसएसआर परिसंवाद श्रृंखला, राजकोषीय शासन एवं सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के विषयों पर अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सूचित सार्वजनिक विमर्श की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेखापरीक्षकों, शिक्षाविदों एवं नीति-निर्माताओं को एक साझे मंच पर लाकर यह पहल सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक लेखापरीक्षा से प्राप्त अंतर्दृष्टि, साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, रचनात्मक नीतिगत संवाद तथा अधिक जागरूक एवं सक्रिय नागरिक समाज के निर्माण में योगदान दे।

* * *